



४/२५१/९२

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

मई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1992/ चैत्र 22, 1914

No. 72]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1992/CHAITRA 22, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के क्रम में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

खाली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

संख्या 11-3/91-एफ. सी.-2--खालीप्रो के बजन में वृद्धि/कारी का
भ्रष्टयन करने के लिए एक समिति और एक उप-समिति की स्थापना
करने संबंधी प्रधिसूचना संख्या 11-3/91-एफ.सी.-2, शिनाक 7-8-1991
का अधिक्रमण करने तुम भारत भरकार में नियंत्र किया है कि इस प्रयोजन
हेतु एक नई समिति गठित की जाए। इससे पहले की समिति और उप-
समिति विवरित मार्गी जाएगी।

1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

1. श्री जे. एम. महाराय, निवेशक (संचलन), खाली मंत्रालय—संयोजक
2. श्री जी. मोहन, प्रबंधक (निगम), भारतीय खाली नियम —सदस्य
3. श्री जे. एम. श्रीवास्तव, उप निवेशक (भं. एवं ग्रन.),
खाली मंत्रालय —सदस्य
4. श्री सी. एम. शिवकारा, प्रबंधन (गुण नियंत्रण), भारतीय
खाली नियम —सदस्य सचिव

1.2 समिति के विवारणीय विषय निम्नलिखित होंगे

- (1) देश के विभिन्न भेंटों में भंडारण के दोगने गेहूं आर. ग्रान/
चावल के बजन में वृद्धि/कारी के तथ्य को तकनीकी जांच करना
और इन खालीप्रो के बजन में वृद्धि/कारी के औचित्य के बारे में
विचार करने के लिए मानदंडों की मिपारिण करना।
- (2) इस बात का अध्ययन करना कि (a) राज्य एजेंसियों द्वारा
केन्द्रीय पूल के लिए स्टाक की बमूली करने समय; (b)
केन्द्रीय पूल से सारतीय खाली नियम पो स्टाक का हस्तांतरण
करने समय; और (c) बाद में भारतीय खाली नियम द्वारा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टाक का हस्तांतरण करने
समय बजन में वृद्धि/कारी की गणना कैसे की जाती है, भगवान
कैसे किया जाता है।
- (3) वस्तुता एजेंसियों से स्टाक नेट के लिए एक प्रणाली तैयार करना
देखि भंडारण के दोगन बजन में वृद्धि गेहूं कारी के दो तथ्यों
के कारण भारतीय खाली नियम को हानि न होगी पाए।
- (4) वस्तुता के विवापरका को तरह भारतीय खाली नियम में तकनीकी
खेती परीक्षा का प्रणाली तैयार करना। ताकि यह गुणश्वत
गुण आ में कि बजन में गेहूं परिवर्तनों के कारण भारतीय
खाली नियम को कम हानि हो।

1.3 सबस्य मौजूदा नियमों/मनुवेशों के अनुरूप उन्हें देय टी.ए./डी.ए. लेने के हकदार होंगे।

1.4 समिति अपनी रिपोर्ट 31-5-1992 तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी।
के. एस. बैंस, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD RESOLUTION

New Delhi, the 31st March, 1992

No. 11-3/91-FC.II.—Government of India have, in supersession of resolution No. 11-3/91-FC. II dated 7-8-1991 setting up a Committee and a sub-Committee to study the phenomenon of gain/loss in weight of foodgrains, decided to constitute a new Committee for the purpose. The earlier Committee as well as Sub-Committee stand dissolved.

1.1 The Committee will consist of the following :—

1. Shri J.M. Sahai, Director (MoU.) Ministry of Food—Convenor.
2. Shri G. Mohan, Manager (Cost) Food Corporation of India.—Member.
3. Shri J.L. Srivastava, DD (S & R) Ministry of Food—Member.
4. Shri C.S. Shivanna, Manager (Quality Control), FCI. — Member Secretary

1.2 The terms of reference of the Committee

will be as follows :—

- (i) To examine technically and quantify the phenomenon of gain/loss in weight of wheat and paddy/rice during storage in different regions of the country and to recommend yard-sticks for considering reasonableness of gain/loss in weight of the foodgrains.
- (ii) To study as to how the weight gained/lost is accounted for/paid for (a) by the State agencies at the time of procurement by them for the Central pool (b) at the time of the transfer of the stocks by them to FCI and (c) subsequently by FCI while transferring stocks to P.D.S.
- (iii) To evolve a system for taking over the stocks from the procuring agencies so that FCI is not put to loss on account of these phenomenon of gain or loss of weight during storage.
- (iv) To evolve a system of technical audit similar to accounts audit in FCI so as to ensure that loss to FCI is minimised on account of such changes in weight.

1.3 The members will be entitled for TA/DA as admissible to them under the existing rules/instructions.

1.4 The Committee will submit its report to the Government by 31-5-1992.

K.S. BAINS, Ad. Secy.